रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है जिनमें भारत के तीन मान चित्रों में शीर्ष भाग में जम्मू और कश्मीर राज्य को पृथक दिखाया गया है : और

(ख) क्या यह भी सच है कि अमरीका की कुछ सरकारी और गैर-सरकारी पत्रिकाओं में भारत के नक्शे से कश्मीर को गायब दिखाया जा रहा है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां । सरकार ने इस मामले को दृढ़ता से विश्व बैंक के साथ उठाया है । सरकार ने इस बात की आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि विश्व बैंक की रिपोर्टों में दिये गये नक्शों में वही प्रणाली अपनाई जानी चाहिये जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई जा रही है । विश्व बैंक ने वाशिंगटन स्थित हमारे मिशन को सूचित किया है कि भविष्य में पूर्ण नक्शों का उपयोग किया जायेगा ।

(ख) जी हां । अमरीका की कुछ गैर-सरकारी पत्रिकाओं में भारत के नक्शे में काश्मीर को न दिखाये जाने से संबंधी मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं । यह हमारी सामान्य नीति है कि ऐसे मामलों को संबंधित प्रकाशन संस्थानों के ध्यान में तुरन्त लाया जाये ताकि उन्हें भारत के नक्शे को सही रूप में प्रस्तुत करने के लिये राजी किया जा सके ।

Ramjanma Bhoomi Babri Masjid dispute

925. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the period of four months announced by the Prime Minister to find a solution to the Ramjanma Bhoomi-Babri Masjid dispute is ending in early June;

(b) if so, what steps Government have taken so far to resolve the dispute; and

(c) what steps Government propose to take in case no solution is found within the stipulated period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (c) In his appeal to the parties involved in the Ramjanma Bhoomi-Babri Masjid issue in February, 1990, the Prime Minister had indicated a broad time frame of four months for holding consultations with the connected groups to resolve the issue in a spirit of mutual accommodation by building a national consensus. With this in view, the Central Government constituted a Committee comprising Prof. Madhu Dandavate, Union Finance Minister, Shri George Fernandes, Union Railway Minister and Shri Mukhtar Anis, Health Minister of the Government of Uttar Pradesh. The Committee's work is in progress.

दिल्ली में निजी बसों के चलाने के लिये शर्तें

926. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग दो वर्ष पूर्व दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिये निजी बसों को दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलाने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) उस समय यह अनुमति किन-किन शर्तों के अधीन दी गई थी ;

(ग) यदि यह अनुमति स्थायी आधार पर नहीं थी, तो इन बसों को दिल्ली